सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 443
13/06/2018

आपदा किसी के वश का नहीं लेकिन प्रयास से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है ताकि लोगों को कम से कम कष्ट सहन करना पड़े :– मुख्यमंत्री

पटना, 13 जून 2018 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद, में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी प्रमंडल एवं जिलों के वरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। समीक्षा बैठक में संभावित बाढ़ 2018 एवं सुखाड़ की स्थिति से पूर्व की तैयारी के विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि द्वारा ऋतुकालीन वर्षा से संबंधित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि बिहार में आकलित औसत वर्षा (1027.6 मि0मी0) का लगभग 93 प्रतिशत वर्षा इस वर्ष संभावित है। बैठक में प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन श्री प्रत्यय अमृत द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया। पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन में बाढ़ की स्थिति में संसाधन मानचित्र, एन0डी0आर0एफ0 सुविधा, तैराकी, गोताखोर, नावों की संख्या, बाढ़ शरणस्थली के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राहत सामग्रियों का दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्ता का चयन, जिला आपातकालीन संचालन केंद्र, फूड पैकेट्स का पैकेजिंग कार्य, नाव/नाव मालिकों के लंबित मजदूरी मामलों पर भी चर्चा की गई। समीक्षा में जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ प्रबंधन हेतु किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें मुख्य रुप से तटों की मरम्मती एवं सुरक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य शिविर के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि एक्सपायरी दवाओं का प्रयोग न हो, मानक दवाएं उपलब्ध करायी जाएं। पशुपालन विभाग द्वारा पशु दवा एवं पशुचारा की उपलब्धता के साथ–साथ पशु राहत शिविर के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, चापाकल की मरम्मती, राहत शिविरों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था आदि से जुड़ी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि चापाकल की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाए ताकि पीने के पानी की कठिनाई न हो। ग्रामीण कार्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों, पुल–पुलियों की मरम्मती संबंधित जानकारी दी गई। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अधिकारियों से विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों में भी बाढ़ आयी थी। पटना शहर की बाढ़ से सुरक्षा के लिए गंगा किनारे पटना टाउन प्रोटेक्शन वॉल जो गोलघर से दानापुर तक विस्तृत है, उसकी मजबूती के लिए भी सतर्क रहने की जरुरत है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान हरेक जिले में अपनी तैयारी के बारे में विस्तार से बताया। बाढ़ से बचाव की तैयारी के साथ–साथ संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने की पूर्ण तैयारी रखनी चाहिए। सुखाड़ की स्थिति में आकस्मिक फसल

योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ध्यान देने की जरुरत है। डीजल अनुदान, नहरों में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, चापाकल की व्यवस्था करने की जरुरत है ताकि सुखाड़ की स्थिति से निपटा जा सके और लोगों को कष्ट न हो। आकस्मिक फसल योजना के संबंध में कृषि विभाग को पूरी तैयारी कर लेने की जरुरत है ताकि लोगों को अधिक से अधिक सहुलियत हो। इस फसल योजना के अंतर्गत और जिन फसलों को शामिल करने की जरुरत है, उसका भी आकलन कर लेना चाहिए। डीजल अनुदान वितरण के लिए जिलाधिकारी भी सतर्क रहें। डीजल खरीद के लिए हमलोग बिचड़ा एवं खरीफ फसल के लिए पांच बार डीजल अनुदान देते हैं। इस बार डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, अतः डीजल के सब्सिडी का रेट बढ़ाकर दिया जाएगा ताकि किसानों को डीजल खरीदने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। कृषि विभाग तत्काल इस पर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित कीजिए ताकि लोगों को सहुलियत हो। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग चापाकल की उपलब्धता एवं उसकी कार्यरत होने की जांच कर लें ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी संबद्ध विभाग के साथ बैठक कर पशुचारा, सुखा राशन, दवा की पूर्ण तैयारी कर लें। राहत सामग्री का दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित कर लिये जायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने वर्षा की अच्छी संभावना जतायी है। हमारी यह प्रार्थना है कि आपका आकलन सही हो ताकि लोगों को राहत मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव एक सप्ताह के बाद अपने–अपने जिलों में जाकर सारी तैयारियों का आकलन एवं समीक्षा कर लें ताकि 30 जून के पूर्व सभी तैयारियॉ कर ली जाय। जिलाधिकारी के आपदा राहत कोष में वित्त विभाग राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे ताकि बाढ़ आपदा की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़ितों को राशि उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने ब्लॉक एवं अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी जिनका स्थानांतरण अभी हुआ है, उन्हें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से बाढ़ राहत संबंधी ट्रेनिंग/ओरियेंटेशन करा दी जाए ताकि वे अपना कार्य बेहतर ढंग से कर सकें। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग को पहले से सचेत रहने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपदा किसी के वश का चीज नहीं है लेकिन अपने प्रयास से उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है ताकि लोगों को आपदा का कष्ट कम से कम सहन करना पड़े।

समीक्षा बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, कृषि मंत्री श्री प्रेम कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री विनोद नारायण झा, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री दिनेश चंद्र यादव, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडेय, ग्रामीण कार्य मंत्री श्री शैलेश कुमार, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री के0एस0 द्विवेदी, विकास आयुक्त श्री शशि शेखर शर्मा, उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री व्यास जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार सहित अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे।

******